



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 13 अगस्त, 2002 ई0

श्रावण 22, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 198/का-2/2002

देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध
प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002

- (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 कड़ी जायेगी।
(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
(3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।
- यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद--
(क) "समुचित प्राधिकारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो;

संक्षिप्त भाव,
प्रारम्भ और जानू
होगा

अध्यासी प्रभाव

परिभाषा

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से निम्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;

(ङ) "रिपोर्ट" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है;

(च) "सचिवालय" का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है;

(छ) "वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

प्रतिकूल रिपोर्ट
की संसूचना और
प्रत्यावेदन के
निपटाने के लिए
प्रक्रिया

4. (1) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर, सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।

(2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में शीघ्र और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पत्र के माध्यम से प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है—परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिए 45 दिन की अग्रतर अवधि की अनुमति दे सकता है।

(3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका-टिप्पणी के लिए भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा—

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।

(4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना—

- (क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए; या
- (ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए सकारण आदेश पारित करेगा।
- (5) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हों तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।
- (6) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।
- (7) जहाँ उपनियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहाँ यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गयी रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा।
- (8) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।
- (9) जहाँ—
- (एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना;
- (दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन;
- (तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिए प्रत्यावेदन के भेजे जाने;
- (चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी; या
- (पांच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लग्गित हो सहाँ ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिए विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिए इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

5. फाइनेशियल हैण्ड-बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम-56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहाँ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित नहीं की जाती है या जहाँ किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम-4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहाँ ऐसी रिपोर्ट को, सम्बन्धित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दस्ततारोंक पार करने और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा। रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना
6. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियाँ करेगा। रजिस्टर का रख-रखाव
7. (1) जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिए विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम शासित

कोई अधिकारी, उसके लिए विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझकर विफल रहता है, वहाँ वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

- (2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हो, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यक्तिगत कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

व्याप्ति

8. नियम 4 के उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 196/Karmic-2/02, dated August 13, 2002 in general information :

No. 196/K.-2/2002

Dated Dehradun, August 13, 2002

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS (DISPOSAL OF REPRESENTATION AGAINST ADVERSE ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS AND ALLIED MATTERS) RULES, 2002

Short title,
Commencement
and Application

1. (1) These rules may be called the Uttaranchal Government Servants (Disposal of Representation against Adverse Annual Confidential Reports and Allied Matters) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to all Government Servants.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context, the expression--

(a) "Appropriate authority" means a person who is empowered by the Government to act as reporting authority, reviewing authority or accepting authority, as the case may be;

(b) "Constitution" means the Constitution of India;

(c) "Government" means the State Government of Uttaranchal.

- (d) "Government Servant" means a person working on a post under the rule making powers of the Governor under the proviso to Article 309 of Constitution other than a post under control of the High Court;
 - (e) "Report" means Annual Confidential Report regarding the work, conduct and integrity of a Government Servant for each year recorded by an appropriate authority, who has seen the performance of the Government Servant for not less than a continuous period of three months;
 - (f) "Secretariat" means the Secretariat of the Government;
 - (g) "Year" means a period of twelve months commencing from the first day of April of a calendar year.
4. (1) Where a report in respect of a Government Servant is adverse or critical, Wholly or in part, hereinafter referred to as adverse report, the whole of the report shall be communicated in writing to the Government Servant concerned by the accepting authority or by an officer not below the rank of reporting authority nominated in this behalf by the accepting authority, within a period of 90 days from the date of recording the report and a certificate to this effect shall be recorded in the report. Communication of adverse report and procedure for disposal of representation
- (2) A Government Servant may, within a period of 45 days from the date of communication of adverse report under sub-rule (1) represent in writing directly and also through proper channel to the authority one rank above the accepting authority hereinafter referred to as the competent authority, and if there is no competent authority to the accepting authority itself, against the adverse report so communicated :
- Provided that if the competent authority or the accepting authority, as the case may be, is satisfied that the Government Servant concerned had sufficient cause for not submitting the representation within the said period, he may allow a further period of 45 days for submission of such representation.
- (3) The competent authority or accepting authority as the case may be, shall, within a period not exceeding one week from the date of receipt of the representation under sub-rule (2), transmit the representation to the appropriate authority, who has recorded the adverse report, for his comments, who shall, within a period not exceeding 45 days from the date of receipt of the representation furnish his comments to the competent authority of the accepting authority as the case may be :
- Provided that no such comments shall be required if the appropriate authority has ceased to be in, or has retired from, the service or is under suspension before sending his comments.
- (4) The competent authority or the accepting authority, as the case may be, shall, within a period of 120 days from the date of expiry of 45 days specified in sub-rule (3) consider the representation alongwith the comments of the appropriate authority, and if no comments have been received without waiting for the comments, and pass speaking orders--
- (a) Rejecting the representation; or
 - (b) Expunging the adverse report wholly or partly as he considers proper.
- (5) Where the competent authority due to any administrative reasons, is unable to dispose of the representation within the period specified in sub-rule (4), he shall report in this regard to his higher authority, who shall pass such orders as he considers proper for ensuring disposal of the representation within the specified period.
- (6) An order passed under sub-rule (4) shall be communicated in writing to the Government Servant concerned.

- (7) Where an order expunging the adverse report is passed under sub-rule (4), the competent authority or the accepting authority as the case may be shall omit the report so expunged.
- (8) The order passed under sub-rule (4) shall be final.
- (9) Where any matter for--
- communication of an adverse report;
 - representation against an adverse report;
 - transmission of representation to the appropriate authority for his comments;
 - comments of the appropriate authority; or
 - disposal of representation against an adverse report is pending on the date of the commencement of these rules, such matters shall be dealt with and disposed of within the period prescribed therefore under this rule.

Explanation-- In computing the period prescribed under this rule for any matters specified in this sub-rule the period already expired on the date of the commencement of these rules shall not be taken into account.

Report not to
be treated
adverse

5. Except as provided in Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules contained in Financial Hand-book, Volume-II, Parts-II to IV, Where an adverse report is not communicated or a representation against an adverse report has not been disposed of in accordance with Rule 4, such report shall not be treated adverse for the purposes of promotion, crossing of Efficiency Bar and other service matters of the Government Servant concerned.

Maintenance of
register

6. The competent authority or accepting authority, as the case may be, or any other authority nominated by him in this behalf, shall maintain a register in such form as may be specified by the Government from time to time and shall make appropriate entries therein.

Penalty

7. (1) Where an officer legally bound to communicate an adverse report to the Government servant concerned or where an officer legally competent to dispose of a representation against an adverse report under these rules, willfully fails to do so within the period prescribed therefore, shall be guilty of misconduct and be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.
- (2) A Section Officer in the Secretariat and an officer or official in charge of an office, other than the Secretariat, shall place the representation, comments of the appropriate authority thereon and other relevant records, if any, before the competent authority or the accepting authority, as the case may be, immediately after their receipt. Any willful default in this behalf, on his part shall be a misconduct and he shall be punishable in accordance with the punishment rules applicable to him.

Savings

8. Any action taken or anything done in respect of any matter specified in sub-rule (9) of Rule 4 before the commencement of these rules, shall be deemed to have been taken or done under the corresponding provisions of these rules.

By Order,

(ALOK KUMAR JAIN)

Secretary.